दुष्यंत ने साधा मज़दूरों पर निशाना, हाथ में लेकर ईएसआई का नकली झुनझुना

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते सप्ताह जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत जिनके एक प्यादे (विधायक अनूप) के पास राज्य का श्रम मंत्रालय भी है, ने पहली बार राज्य के मज़दूरों को साधने का एक खोखला प्रयास किया। सरकारी विज्ञापनभोगी अखबारों को प्रेस विज्ञप्ति देकर छपवाया गया कि दुष्यंत राज्य के ईएसआई कवर्ड मज़दूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिये बहुत प्रयास कर रहे हैं। प्रेसनोट में यह दर्शाया गया है कि उनके प्रयासों से बावल, गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ, रोहतक, हिसार आदि में नये अस्पताल व डिस्पेंसरियां खुलने जा रहे हैं।

दरअसल यह सब हकीकत से कोसों दूर जुमलेबाज़ों द्वारा तैयार करके छपवाया गया एक राजनीतिक एवं भ्रामक शिगूफ़ा मात्र है। दुष्यंत द्वारा न तो इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है और न ही नया कुछ हो रहा है। बावल और बहादुरगढ़ के जिन अस्पतालों का राग दुष्यंत अलाप रहे हैं उनमें बावल का शिलान्यास बरसों पहले भारत के महान जुमलेबाज़ नरेन्द्र मोदी कर चुके हैं। यह ड्रामा उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र लोग़ों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिये 12 फ़रवरी को किया था। रही बात सोनीपत, रोहतक व हिसार की, तो उनके लिये अभी ज़मीन की तलाश हो रही है, जो कि बीते कई बरसों से हो रही है और आगामी कई बरसों तक होती रहेगी; होना-जाना खाक नहीं, बस चुनावी सभाओं में इनका चर्चा होता रहेगा। मजे की बात तो यह है कि शिलान्यास के बाद बावल में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है। दूसरे, इस पूरे गोरख धंधे से हरियाणा सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। ज़मीन खरीदने से लेकर निर्माण कार्य तक सारा काम खुद ईएसआई कार्पोरेशन के जिम्मे है।

उपमुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत इस शहर के अलावा गुड़गांव में बीसियों बार आ चुके हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने यहां के अस्पताल व डिस्पेंसरियों की दुर्दशा का नज़ारा तक देखने की जहमत नहीं उठाई। और तो और यहां आने पर कभी मज़दूर संगठनों से बात करने तक की भी उन्होंने कोई जरूरत महसूस नहीं की। नये अस्पताल व डिस्पेंसरियां खोलने की बात तो छोड़िये, उनके विभाग (ईएसआई हेल्थ केयर) से तो मौजूदा ब्यवस्था ही नहीं चल पा रही, न डॉक्टर हैं न स्टाफ़ व अन्य साजो-सामान। हां, दुष्यंत को झटके में एक काम तो करना जरूर आता है, जो उन्होंने पिछले दिनों करके भी दिखा दिया है। जैसे-तैसे चल रही तमाम डिस्पेंसरियों को बंद करके सारे स्टाफ़ को बिना किसी काम के हिसार व पानीपत बुला कर बैठा दिया, जहां उनकी कोई उपयोगिता नहीं।

दुष्यंत को मज़दूरों की याद आई कैसे यकायक

विदित है कि दुष्यंत हर माह ग्रीवेंस कमेटी के माध्यम से फ़रीदाबाद वासियों के दुख 'निवारण' करने आते हैं। किस-किस के दुख का निवारण हुआ यह तो पता नहीं, परन्तु ईएसआई अस्पताल सेक्टर 8 के एक डॉक्टर अखिल महाजन ने ईएसआई कवर्ड मज़दूरों के दुखों का निवारण करने हेतु किसी तरह जुगाड़ लगाकर दुष्यंत तक पहुंच बनाई। डॉक्टर महाजन ने जब स्थानीय ईएसआई अस्पताल व डिस्पेंसरियों की व्यथा-कथा सुनानी शुरू की तो उपमुख्यमंत्री जी बोर होने लगे तो डॉ. महाजन को चंडीगढ आने को कह दिया। क्योंकि उनकी न तो मज़दूरों में कोई रूचि है और न ही ईएसआई में। हो सकता है उन्होंने ईएसआई का नाम भी इन्हीं दिनों में सुना हो। इसकी व्यवस्था कैसे चलती है, कौन चलाता है, पैसा कहां से आता है और इसके द्वारा दसियों हज़ार लोग़ों को रोज़गार देने के साथ-साथ राज्य की आधी से अधिक आबादी को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है।

दुष्यंत चौटाला

खैर, जो भी हो डॉ. महाजन चंडीगढ जा पहुंचे दुष्यंत के साथ। दो-चार मिनट बात करने के बाद उन्होंने डॉ. महाजन को श्रम सचिव वीएस कुंडू व ईएसआई हैल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर अनिल मलिक के हवाले कर दिया। जाहिर है दुष्यंत को इतनी फुर्सत व समझ कहां कि जो इतने गंभीर मसले की ओर ध्यान दे पाते। उधर वीएस कुंडू को भी इस विषय की जानकारी कम होने के चलते कमान डॉ. मलिक के हाथ में आ गयी। धूर्तता में पूरी महारत के चलते इस वार्ता में डॉ. मलिक ने महाजन के पंजे ही नहीं लगने दिये। उन्होंने डॉ. महाजन को यह समझा कर लौटा दिया कि ईएसआई कार्पोरेशन प्रति बीमाकृत (आईपी) पर 3000 रुपये वार्षिक से अधिक खर्च नहीं करने देती और वे लोग इसी सीमा के भीतर रहते हुए खर्च कर रहे हैं।

डॉ. महाजन के तर्कों को काटते हुए सचिव कुंडू और डॉ. मलिक ने उन्हें समझाया कि कार्पोरेशन जो फ़रीदाबाद स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा गुड़गांव के दो अस्पतालों पर खर्च कर रही है वह भी इसी 3000 की सीमा में गिना जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कार्पोरेशन कोई भी अस्पताल या डिस्पेंसरी चलाने ज़मीन व उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का खर्च उसमें शामिल नहीं करती है जो प्रति आईपी खर्च करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। विदित है कि फ़िलहाल हरियाणा में 24 लाख आईपी हैं जिनके वेतन का 4 प्रतिशत ईएसआई कार्पोरेशन वसूलती है, पहले यह साढे 6 प्रतिशत होता था। बजाय सेवायें बेहतर करने के ढाई प्रतिशत योगदान घटाना केन्द्र सरकार ने बेहतर समझा। इस दर से भी 24 लाख मज़दूरों से ईएसआई कार्पोरेशन को वर्ष 2019-20 में कुल 1148 करोड़ 95 लाख की वसूली हरियाणा से हुई। यदि 3000 रु. प्रति आईपी वाला फ़ार्मूला भी मानें तो भी 24 लाख के लिये 720 करोड़ खर्च करने का हक तो हरियाणा का बनाता ही था। इसके बरक्स हरियाणा के हेल्थ केयर का बजट 2019-20 में बनाया गया मात्र 208 करोड़ और 2020-21 का 219.85 करोड़, इस में से भी 10-20 करोड़ लैप्स होने का पूरा खतरा है। इसके आगे 2021-22 का परोपोज़्ड बजट 238.9 करोड़ है, वास्तव में खर्च इससे भी कहीं कम होने वाला है।

इससे भी भयंकर कहानी देखनी हो तो ज़रा पीछे की ओर चलिये, 2017-18 का बजट था 132.51 करोड़, 2018-19 का बजट था 166.97 करोड़। इससे भी कहीं अधिक मजे की बात यह है कि 31 मार्च 2018 को हरियाणा में आईपी की संख्या थी 29 लाख 70 हज़ार और इनसे वसूली की दर थी उस वक्त साढे छः प्रतिशत अर्थात राज्य के मज़दूरों से उस वक्त वसूले जा रहे थे करीब 2100 करोड़ सालाना और राज्य सरकार अपना हेल्थ केयर बजट बना रही भी मात्र 132.51 व 166.97 करोड़ का। यह सब क्या था राज्य के हेल्थ केयर निदेशालय की हरामखोरी व उसके ऊपर बैठी सरकार की नालायकी।

3000 खर्च की सीमा के साथ-साथ कार्पोरेशन की नियमावली यह भी प्रावधान है कि राज्य यदि कोई बड़े महत्वपूर्ण उपकरण एवं आवश्यक साजो-सामान खरीदना चाहे तो इस सीमा से आगे भी बढा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कार्पोरेशन केवल पूरा वार्षिक बजट खर्च होने पर ही अपना 8/7 हिस्सा देगा, बल्कि हर तिमाही के खर्च पर ही लेन-देन हो जाता है।

दिल्ली में प्रति आईपी 7055 रुपये

दिल्ली में 15.96 लाख आईपी पर कार्पोरेशन 7055 रुपये प्रति आईपी खर्च करती है जो कि पूरे का पूरा कार्पोरेशन द्वारा ही वहन किया जाता है। वहां कोई सरकार इस खर्च में कोई हिस्सा नहीं बटाती, जबकि हरियाणा में प्रति आईपी 800 रुपये से भी कम ही रहता रहा है और वसूली भरपूर। केरल, तमिलनाडू व बंगाल की सरकारें बेहतर कार्यकुशलता के बल पर प्रति आईपी 3000 वार्षिक से भी अधिक खर्च करके अपने यहां बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करा रही हैं। मजे की बात तो यह है कि इन तीनों ही राज्यों में डबल ईंजन की सरकारें नहीं हैं, केन्द्र सरकार की घुर विरोधी सरकारें होने के बावजूद ईएसआईसी से अपना हक वसूल कर रही हैं। जबकि हरियाणा में डबल ईंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही।

बीते ढाई साल से रेबीज़ ईंजेक्शन नहीं

हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर अनिल मलिक से यह पूछने वाला सरकार में कोई नहीं है कि बीते करीब ढाई साल से उन्होंने रेबीज़ (कुत्ता काटे के) इन्जेक्शन जैसी महत्वपूर्ण दवा की खरीद क्यों नहीं की? विदित है कि कुत्ता या बंदर काटे के बीसियों हजार केस हर साल ईएसआई में आते हैं, सबको कह दिया जाता है कि बाजार से खरीद कर लगवा लो, रिएम्बर्स कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था में एक मज़दूर के लिये रिएम्बर्स कराना इतना आसान नहीं है, इसके चक्कर में वह कहीं अधिक नुक्सान अपनी दिहाड़ियों का कर बैठता है। बीते दो साल में खुद इस संवाददाता ने तीन बार फ़ोन पर डॉ. मलिक से बात की है। शुरू में तो वह मामले से ही अनभिज्ञता जताते हैं;फ़िर कहते हैं कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों (एमएस व सीएमओ) को लोकल खरीद के आदेश दे रखे हैं जबकि स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि उनके पास इस बाबत न तो पर्याप्त अधिकार हैं और न ही बजट । परिणामस्वरूप ईएसआई को अपने वेतन का चार प्रतिशत देने के बावजूद इलाज बाहर से कराना पड़ता है। यह मामला केवल रेबीज बेक्सीन का नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसी दवायें हैं जो डिस्पेंसरियों व अस्पताल में उपलब्ध नहीं है।

डॉक्टर मलिक साहब से पूछा जाय कि ईएसआई कार्पोरेशन ने फ़रीदाबाद से सेक्टर 8 में जो 200 बेडेड अस्पताल की इमारत बना कर इन्हें सौंप रखी है, उसमें हो क्या रहा है? वहां बरसों से ओटी को ताला लगा है, 10-15 से अधिक मरीज़ कभी वहां दाखिल नहीं हुए, यहां तक कि कोविड के इस दौर में, जब अस्पतालों में बेडों की मारा-मारी चल रही थी, यहां कव्वे बोल रहे थे, क्योंकि यहां न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं न अन्य स्टाफ़। इसके चलते एनएच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर मरीज़ों का भारी दबाव बना रहता है, जिन्हें मामूली से इलाज की भी जरूरत होती है उन्हें भी मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। जाहिर है ऐसे में मेडिकल कॉलेज की सेवाओं पर अवांच्छित दबाव बढता है।

बीते सात वर्ष से इस पद को घेरे बैठे तथा आगामी सात साल तक और बने रहने वाले डॉ. मलिक से यह भी तो कोई पूछे कि जब हरियाणा में 29 लाख 70 हजार मज़दूर अपने वेतन का साढे छः प्रतिशत टैक्स ईएसआई को दे रहे थे तो ये साहब 900 करोड़ का बजट बनाने की बजाय मात्र 125-150 करोड़ का ही बजट क्यों बनाते थे? इतना ही नहीं उसमें से भी 10-20 करोड़ लैप्स हो जाते थे? इतना ही नहीं उनकी काहिली व धूर्तता के चलते न केवल इनका पूरा दफ़्तर हरामखोरी का अड्डा बना है बल्कि राज्य भर में फ़ैला इनका स्टाफ़ अपने ही अन्य कर्मचारियों को नोचने-खाने की फ़िराक में लगा रहता है।

बीते सात साल से जो डॉक्टर व अन्य कर्मचारी ईएसआई कार्पोरेशन में समाहित हो गये थे उनको तब तक रिलीव नहीं किया जब तक उन्होंने इनके यहां मत्था नहीं टेका या उच्चाधिकारियों से इनको फटकार नहीं लगवाई। उसके बावजूद उनकी आर्थिक लाभ सम्बन्धित कुछ फ़ाइलें इनका दफ़्तर अभी तक दबाये बैठा है, इस आस में कि शायद कोई कुछ दे जाय।

सन फ्लैग अस्पताल के ग्राहकों की कतार में अब ईएसआईसी भी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 16 ए स्थित 8 एकड़ के प्लॉट पर बने सनफ्लैग अस्पताल को 2017 में 'हूडा' ने रिज्यूम (जब्त) कर लिया था। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने इसे बेचने के लिये टेंडर आमंत्रित किये थे जिस बाबत 'मज़दूर मोर्चा' के 4 जुलाई के अंक में प्रकाशित किया गया था। बेचने की इस प्रक्रिया के विरोध में शहर के अनेकों जागरूक नागरिकों ने प्रदर्शन किया था।

अब, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी पर यदि भरोसा करें तो ईएसआई कार्पोरेशन इस अस्पताल को लेने का प्रयास कर रही है। सूत्र बताते हैं कि एनएच -3 स्थित मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष 17 स्नातकोत्तर कोर्स यानी एमबीबीएस के बाद की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इसके साथ-साथ ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी इलाज भी शुरू करना चाहती है, इन सबके लिये मौजूदा मेडिकल कॉलेज परिसर छोटा पड़ रहा है। इसलिये कार्पोरेशन चाहती है कि 8 एकड़ के इस अस्पताल को खरीद कर अपनी विशिष्ट सेवाओं का विस्तार किया जाय।

हरियाणा की खट्टर सरकार की नीयत यदि साफ़ है और वह किसी चिकित्सा व्यापारी से सांठ-गांठ नहीं करे बैठी है तो उसे तुरंत यह अस्पताल ईएसआईसी को सौंप देना चाहिये। वैसे तो कार्पोरेशन इसका वाजिब दाम देने को तैयार है जो किसी भी चिकित्सा व्यापारी से कम नहीं होगा, परन्तु फ़िर भी खट्टर सरकार को यह अस्पताल ईएसआईसी को उनकी उन सेवाओं के बदले मुफ़्त में दे देना चाहिये जो उसने बीते दो वर्षों में इसे कोविड-19 के लिये कब्ज़े में लेकर प्राप्त की हैं। इससे जनता की वह मांग भी पूरी हो जायेगी जिसके द्वारा इसे सरकार द्वारा चलाने के लिये कहा गया था; यानी खट्टर सरकार इस अस्पताल को चलाने की जिम्मेवारी से भी बच जायेगी और यह किसी व्यापारी के हाथों में भी नहीं जायेगा।

सनफ्लैग की वास्तविक स्थिति

खोजबीन करने पर इस संवाददाता ने पाया कि 'हूडा' द्वारा 2017 में रिज्यूम किये जाने के तुरंत बाद इसके मालिकान 'भारद्वाज' चेरिटेबल ट्रस्ट ने उसी वक्त इसके विरुद्ध 'हूडा' प्रशासक के सामने अपील डाल दी थी। ट्रस्ट के वकील जगबीर भडाना ने बताया कि अब तक 25 तारीखें लग चुकी हैं लेकिन कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। 'हूडा' द्वारा टेंडर निकालने को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में यचिका डाल रखी है कि जब तक उनकी अपील का फैसला नहीं हो जाता और ट्रस्ट मौके पर मालिक काबिज है तो टेंडर कैसे निकाला जा सकता है?

सनफ्लैग द्वारा इसे एसआरएस ग्रुप को बेच दिये जाने बाबत वकील साहब का कहना है कि इसे बेचा नहीं गया था, केवल प्रबन्धन चलाने के लिये दिया गया था, ट्रस्ट आज भी इसका मालिक काबिज है

इस खेल में दूसरा पेच कृष्णलाल गेरा का है। उन्होंने 2007 में ही हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि जिन शर्तों पर ट्रस्ट को भूखंड अलॉट किया गया है उनका घोर उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आवंटन रद्द किया जाये। ट्रस्ट वहां से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों पर ट्रस्ट को राहत देने को कही थी, ट्रस्ट उन्हें पूरा नहीं कर पाया था। उधर सनफ्लैग अस्पताल में कार्यरत रहे कर्मचारियों ने भी लम्बी कानूनी लड़ाई जीत कर अपने बकाया की वसूली हेतु लिक्विडेशन के आदेश प्राप्त कर रखे है। यानी मामला पूरी तरह से घालमेल एवं लफ़ड़ेबाज़ी का बना हुआ है।

गौरतलब है कि एक तरफ़ तो यह अस्पताल एक चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है, दूसरी तरफ़ ट्रस्ट इसे चला पाने में पूरी तरह से नाकाम है। कभी इसे मेट्रो ग्रुप को किराये पर दिया जाता है, कभी ट्रस्ट खुद चलाने के प्रयास में नाकाम होकर एसआरएस जैसे उस, फ्रॉड ग्रुप को चलाने के लिये सौंपता है जिसका मेडिकल व्यवसाय से कोई ताल्लुक नहीं, तो फ़िर ट्रस्ट क्यों इससे चिपका रहना चाहता है? बताते हैं कि ट्रस्टी रहते भी लंदन में हैं।

इन हालात के मद्देनजर इस अस्पताल को यदि ईएसआईसी को सौंप दिया जाय तो क्या हर्ज है? इससे बढिया न तो कोई प्रबन्धन हो सकता है और न ही चैरिटी।

कोविड की दो जानलेवा लहरों से ग्रसित नागरिकों को जहां व्यापारिक अस्पतालों ने जमकर लूटा था। वहीं दूसरी और ईएसआईसी के इस मेडिकल कॉलेज ने उन हजारों नागरिकों की जान बचाई थी। जिनका ईएसआईसी में कोई योगदान नहीं था। इसका सारा खर्चा मजदूरों द्वारा दिये गये योगदान के बल पर ईएसआईसी ने भुगता था।